ISSN: 2584-0231(Online)
International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology
Volume 4 | Issue 8 | August 2026
Available online at: https://ijmrast.com
DOI: https://doi.org/10.59828/ijmrast.v4i8.305

कृषि विकास से विकसित भारत की ओर: 2047 के लक्ष्य हेतु आवश्यक रणनीतियां

धनंजय कुमार मौर्य
असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, बी०एन०के०बी० पी०जी०कॉलेज अकबरपुर अंबेडकर नगर
Email: dkmmaurya@gmail.com

Abstract (सार)

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी साँझा राष्ट्रीय आकांक्षा एक विकसित समावेशी और सशक्त राष्ट्र " विकसित भारत " की परिकल्पना है। बदलाव के इस दौर में कृषि क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका होगी क्योंकि रोटी और आजीविका दोनों के लिए हम इस पर निर्भर हैं। यह क्षेत्र भारत की सभ्यता और संस्कृति में बसा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है ।

कृषि क्षेत्र को पूर्णत विकसित किए बिना हम 2047 तक भारत को विकसित नहीं बना सकते। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। संसाधनों के कुशल उपयोग जैविक खेती फसल विविधिकरण और लचीलेपन जैसे प्रमुख कारकों के साथ खाद्य सुरक्षा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतत कृषि पद्धतियां महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इन सभी को अपनाकर हम आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे किसानों का सशक्तिकरण होगा, प्रथाएं आधुनिक बनेगी,पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी, तथा एक शुद्ध प्रौद्योगिकी सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का अविर्भाव होगा जो ग्रामीण भारत में समृद्धि लाकर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा।

मुख्य शब्द: *जैविक खेती, फसल विविधीकरण, खाद्य सुरक्षा, आत्म निर्भर कृषि*

प्रस्तावना

भारत में कृषि की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी भारतीय इतिहास में उल्लेख किया गया है कि चावल और कपास सिंधु घाटी में खेती की जाने वाली दो फसलें थी । भारत की स्वतंत्रता के बाद देश ने कृषि क्षेत्र में अत्यधिक विकास किया है । 1960 के मध्य के दौरान भारत अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से आयातित भोजन पर निर्भर था । लेकिन 1965 और 1966 के सूखे ने भारत को अपनी कृषि नीति में सुधार के लिए राजी कर लिया ।[12]

भारत ने गेहूं और चावल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व में अपनी रैंक स्थापित की है । कृषि में सफलता का मुख्य कारण भारत का सिंचाई नेटवर्क है । पिछले 50 वर्षों में सिंचाई नेटवर्क में सुधार ने मानसून पर निर्भरता को कम करने तथा खाद्य सुरक्षा मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है । भारत सरकार कई वर्षों से कृषि ढांचे पर कार्य कर रही है और कृषि में अपना निवेश बढ़ा रही है । किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं शुरू की गई है । यह योजनाएं उन्हें मौसम की स्थिति, कृषि पर जलवायु प्रभाव ,जैविक खेती और कृषि के प्रबंधन के बारे में जानने को शिक्षित करती हैं ।

विकसित भारत @ 2047 का स्वप्न केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि भारत को वैश्विक पटल पर एक सशक्त आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का एक महासंकल्प है इस संकल्प की सिद्धि के लिए कृषि क्षेत्र को आधारशिला माना गया है । भारत की लगभग 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है । ऐसे में बिना कृषि का कायाकल्प किये विकसित भारत की परिकल्पना अधूरी है ।नीति आयोग के दृष्टिकोण के अनुसार 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन और रणनीतिक हस्तक्षेप अनिवार्य है ।

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन घटती जोत और पारंपरिक संसाधनों के अत्यधिक गंभीर दोहन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए कृषि विकास से विकसित भारत की रणनीति तीन मुख्य स्तंभों पर टिकी है- तकनीकी नवाचार, मूल्य संवर्धन और समावेशी नीतिगत सुधार ।

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है । देश 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है ।हमारी साँझा राष्ट्रीय आकांक्षा एक विकसित समावेशी और सशक्त राष्ट्र विकसित भारत की परिकल्पना है । बदलाव के इस दौर में कृषि क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका होगी क्योंकि रोटी और आजीविका दोनों के लिए हम इस पर निर्भर हैं । यह क्षेत्र भारत की सभ्यता और संस्कृति में बसा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है ।

कृषि क्षेत्र को पूर्णतया विकसित किए बिना हम 2047 तक भारत को विकसित नहीं बना सकते इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घटकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा संसाधनों के कुशल उपयोग जैविक खेती फसल विविधीकरण और लचीलेपन जैसे प्रमुख कारकों के साथ खाद्य सुरक्षा पर्यावरणीय स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सतत कृषि पद्धतियां महत्वपूर्ण बन जाती हैं इन सभी को अपनाकर हम आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं इससे किसानों का सशक्तिकरण होगा प्रथाएं आधुनिक बनेगी पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी तथा एक शुद्ध प्रौद्योगिकी की सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का अविर्भाव होगा जो ग्रामीण भारत में समृद्धि लाकर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा ।[6]

प्रस्तुत शोध लेख में उन आवश्यक रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है जो भारतीय कृषि को निर्वाह खेती से निकलकर एक लाभप्रद कृषि व्यवसाय मॉडल में परिवर्तित कर सकती है इसमें डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे नैनो फर्टिलाइजर्स और पीएम प्रणाम जैसी योजनाएं महत्वपूर्ण होगी ।यह लेख इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारतीय किसानों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा सकता है ताकि 2047 तक भारत न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर रहे बल्कि दुनिया की फूड बास्केट बनकर भी उभरे ।[4]

यह शोध पत्र कृषि विकास की वर्तमान स्थिति प्रमुख चुनौतियों सरकारी पहलों नीतिगत नवाचारों तथा नीतिगत सुधारो का विश्लेषण करता है साथ ही यह स्पष्ट करता है कि कैसे कृषि क्षेत्र में समावेशी टिकाऊ और लाभकारी विकास भारत को विकसित राष्ट्र की दिशा में अग्रसर कर सकता है ।

पटेल निदा ,चेरे माधुरी, सूर्यवंशी पंकज ने अपनी शोध लेख " प्राकृतिक खेती से सतत कृषि विकास " मई 2024 में बताया है कि पिछले कई वर्षों से खेती में हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है इससे कृषि में लागत बढ़ रही है और मृदा के प्राकृतिक स्वरूप में भी हानिकारक बदलाव हो रहे हैं रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता होते जा रहे हैं तथा मृदा के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है मृदा की इस घटती उर्वरक क्षमता को देखते हुए जैविक खाद का उपयोग जरूरी हो गया है ।

सिंह प्रभा ने अपने शोध लेख " कृषि विकास में कृषि साख के साधनों का समीक्षात्मक अध्ययन: सतना जिले के विशेष संदर्भ में " बताया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि कई उद्योगों का आधार है परंपरागत कृषि को आधुनिक कृषि में बदलने के लिए कृषि साख अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ।इससे कम श्रम और समय से अत्यधिक उत्पादन संभव होगा । इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने से कृषकों की रुचि और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी ।

डा० रामप्पा के० टी०,डॉक्टर उदय कुमार निदोनी,डॉक्टर शरद गौड़ा हीरे गौदर ,डॉक्टर विजय कुमार पालेड व डॉक्टर ए० वी० कारे गौदर ने अपने शोध लेख "कृषि के उभरते मुद्देऔर संभावित कृषि इंजीनियरिंग समाधान" में बताया है कि ग्रामीण कृषि कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है । ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने व आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने के लिए कृषि में इंजीनियरिंग हस्तक्षेप करना आवश्यक है । इन नवीन बदलावों से कृषि में लाभप्रदता बढ़ेगी व टिकाऊ कृषि का विकास होगा ।

दत्त बिंदिया एवं शर्मा नीतू ने अपने शोध लेख "कृषि के विकास में सोशल मीडिया की भूमिका" मेंबताया है कि कृषि क्षेत्र में भी सोशल मीडिया कई प्रकार से सहायक बनाकर बड़े आयाम स्थापित करने में सक्षम है । वर्तमान समय में नवीन तकनीकों को सांझा करने में व समयबद्ध प्रासंगिक व विश्वसनीय सूचनाओं को पहुंचाने में सोशल मीडिया की भूमिका अतयन्त महत्वपूर्ण होगी जिससे कृषि क्षेत्र को विश्वस्तरीय मुकाम तक पहुंचा जा सकता है ।

प्रोफेसर पद्मानंद वी०नेअपनी शोध लेख "विकसित भारत के लिए कृषि नीति और बजटीय पुनर्संरचना" में बताया है कि भारतीय बजट का संबंधित कृषि घटक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किसानों के साथ प्रयोज्य आय बढ़ाने, उर्वरक इनपुट पर सब्सिडी देने और एम०एस०पी० का प्रस्ताव करने पर केंद्रित है । लेखक ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कुल कृषि बजटीय परिव्यय का बहुत कम भाग ही उत्पादकता बढ़ाने वाले मूलभूत संरचना और निवेश की ओर उन्मुख है । इसे और बढ़ाकर ही विकसित भारत की संकल्पना को बढ़ावा मिल सकता है ।

यह शोध लेख मिश्रित शोध पद्धति पर आधारित है - इसमें गुणात्मक विश्लेषण व मात्रात्मक विश्लेषण दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया गया है ।गुणात्मक विश्लेषण से नीतियों योजनाओं और कृषि चुनौतियों के विवरण पर प्रकाश डाला गया है।मात्रात्मक विश्लेषण से कृषि उत्पादन ,आय ,निर्यात तथा प्रगति के आंकड़े लिए गए हैं । डेटा विश्वसनीय सरकारी स्रोतों, राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी, नीति दस्तावेजों और कृषि विशेषज्ञों के प्रतिवेदन पर आधारित है ।

इस शोध लेख का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कृषि के वर्तमान स्वरूप का विश्लेषण करना, 2047 तक कृषि उत्पादन, आय, नवाचार और निर्यात लक्ष्यों का निर्धारण करना, कृषि विकास में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा प्रभावी रण-नीतियों का प्रस्ताव जो भारत को 2047 तक विकसित कृषि -आर्थिक राष्ट्र बना सके ।

भारत की खेती केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था सामाजिक ढांचे और राष्ट्रीय विकास की बुनियाद है । खेती मजबूत होंगी तभी गांव संभलेंगे वह सशक्त होंगे और देश की अर्थव्यवस्था टिकाऊ बन पाएगी । देश की लगभग दो तिहाई आबादी आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है लेकिन यहां इनोवेशन की गति कम है । वस्तुतः गांव और किसान की खुशहाली जितना बजट पर निर्भर करती है उतना ही किसानों की मनोदशा पर भी । खेती को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर ही स्थिति तेजी से बदल सकती है ।यह किसानों को समझना होगा और केंद्र से लेकर राज्य सरकारों को प्रोत्साहन के जरिए इसे बढ़ावा देना होगा खेती की सबसे बड़ी कमजोरी कम उत्पादकता दर है और इस दिशा में सरकारों की ओर से बहुत कम काम हो रहे हैं । कुल उत्पादन बढ़ने के बावजूद उत्पादकता में भारत आज भी चीन, इजरायल ,अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों से काफी पीछे है औसतन दो से ढाई गुना तक कम उत्पादकता है । गेहूं, धान ,दाल और तिलहन की उपज वैश्विक औसत से कम है । लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं जिनके पास सीमित जमीन है[7] ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने का रास्ता सिर्फ दो है पहला - प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना दूसरा - उपज की बेहतर कीमत सुनिश्चित करना । लेकिन दोनों मोर्चे पर प्रगति सीमित है उत्पादकता बढ़ाने पर ही किसान अपनी जमीन पर पारंपरिक उपज की बजाय बाजार की मांग के अनुसार फसल बोएंगे विविधीकरण करण के लिए सरकार कृषि विधेयक लेकर आई थी । लेकिन वह राजनीति की भेंट चढ़ गया ऐसे में विविधीकरण करण के लिए प्रोत्साहन और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए । एम एस पी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्य डॉक्टर विनोद आनंद का कहना है कि गांव की समृद्धि के लिए किसानों को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है फसलों की मार्केटिंग नीति में बदलाव हो । को -ऑपरेटिव एक्सपोर्ट व कमोडिटी जोन बनाए जाने चाहिए ,ताकि फसलों की खरीद निर्यात और वैल्यू एडिशन की प्रक्रिया आसान हो सके।खाद्यान्न उत्पादन और निर्यात बढ़ा है लेकिन उसका लाभ किसानों तक नहीं पहुंचा । खेती की लागत और बिक्री खर्च लगातार बढ़ रहे हैं । सहकारिता से किसानों को उपज की विभाजित कीमत मिल सकेगी ।

भारत में कृषि की वर्तमान स्थिति (Current Scenario) उत्पादन, GDP योगदान और चुनौतियाँ -

भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति

1 -कृषि का आर्थिक योगदान

वर्तमान में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 18–20 प्रतिशत है। हालांकि रोजगार में इसका योगदान लगभग 45 प्रतिशत तक है, जो उत्पादकता की कमियों को दर्शाता है। कृषि वृद्धि दर औसतन 3–3.5 प्रतिशत के बीच रही है, जबकि विकसित भारत के लक्ष्य हेतु कम से कम 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि आवश्यक मानी जाती है।[3]

Table 1: भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति बनाम 2047 लक्ष्य

संकेतक	वर्तमान स्थिति (लगभग)	2047 लक्ष्य
कृषि GDP वृद्धि	3–3.5%	5%+
कृषि निर्यात में हिस्सेदारी	6–7%	20%
कृषि R&D निवेश (GDP का %)	0.4%	1%
औसत जोत आकार	1.08 हेक्टेयर	संगठित/समेकित खेती
सिंचाई कवरेज	~52%	75–80%

Source: Economic Survey, ICAR, MoAFW[1]

2 - संरचनात्मक समस्याएँ

भारतीय कृषि कई संरचनात्मक चुनौतियों से ग्रस्त है—

1. भूमि का विखंडन:

   औसत जोत आकार लगातार घट रहा है, जिससे यंत्रीकरण और आधुनिक तकनीक अपनाना कठिन होता जा रहा है।

2. सिंचाई पर निर्भरता:

   आज भी लगभग आधी कृषि वर्षा पर निर्भर है, जिससे उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है।

3. कम तकनीकी अपनाने की दर:

   छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि तकनीकों से वंचित हैं।

4. बाजार तक सीमित पहुँच:

   किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

3. कृषि विकास की आवश्यकता: 2047 के संदर्भ में

2047 तक भारत की जनसंख्या लगभग 160 करोड़ होने का अनुमान है। ऐसे में—

- खाद्य मांग में भारी वृद्धि होगी
- पोषण सुरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाएगी
- प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा[13]

इन परिस्थितियों में कृषि विकास की रणनीति केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकती। इसे आय, पोषण, पर्यावरण और तकनीक—चारों आयामों को संतुलित करना होगा।

कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों की वास्तविक आर्थिक विकास दर लगभग 3.5% तक सीमित रही है, जो विकसित भारत के 5% वार्षिक वृद्धि लक्ष्य से काफी कम है। [10]

कृषि निर्यात मौजूदा स्तर में केवल लगभग 6% पर है, जबकि 2047 लक्ष्य में इसे लगभग 20% तक विस्तारित करने की योजना है।

औसत भूमि holding का आकार घटकर 1.18 हेक्टेयर से लगभग 0.6 हेक्टेयर तक गिरने की संभावना है, जिससे संसाधन प्रबंधन का दबाव बढ़ेगा।

Table 2: दशक वार उत्पादन के आंकड़े[2]

अवधि / वर्ष	कुल खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	मुख्य विवरण
1950 - 51	50.8	स्वतंत्रता के बाद की प्रारंभिक स्थिति
1960 - 61	82 .0	उत्पादन में धीमी वृद्धिआयात पर निर्भरता
1970 -71	108 .4	हरित क्रांति का शुरुआती प्रभाव
1980 - 81	129 .6	खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की ओर
1990 - 91	176 .4	अच्छे मानसून और उन्नत तकनीकों परिणाम
2000 - 01	196 .8	उत्पादन में निरंतर स्थिरता और वृद्धि
2013 - 14	265 .0	आधुनिक कृषि सुधारों का दौर
2023 - 24	332 .3	अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड
2024 -25 अग्रिम अनुमान	357.73	सर्वोच्च ऐतिहासिक रिकॉर्ड

वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं और चावल उत्पादक राष्ट्र है । भारत सरकार ने आगामी फसल वर्ष 2025 - 26 के लिए 354 . 64 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है ।

2047 के लिए लक्ष्य और रणनीतिक रूपरेखा (Targets & Strategic Framework)

कृषि विकास के लक्ष्य

1- कृषि और सहायक क्षेत्रों में लगातार 5% वार्षिक वृद्धि।

2- कृषि निर्यात का हिस्सा 20% तक बढ़ाना।

3- कृषि GDP में अनुसंधान और नवाचार पर निवेश को वर्तमान ~0.4% से ~1% तक विस्तारित करना।

आवश्यक नीतियाँ और रणनीतियाँ (Required Policies & Strategies)

1. कृषि अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी

कृषि अनुसंधान को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना और कृषि क्षेत्र में तकनीक-आधारित नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। उदाहरण: ICAR, कृषि विश्वविद्यालय और शोध संस्थान कृषि उत्पादन और लागत नियंत्रण के लिए संयुक्त अनुसंधान में कार्यरत हैं। AI, डेटा-आधारित निर्णय समर्थन तकनीकें और precision farming को अपनाना।

2. विविध और पौष्टिक कृषि संरचना (Diversified & Nutrient-Rich Production)

ICAR-NIAP के शोध के अनुसार पारंपरिक फसलों से संसाधन पुनःआवंटन कर पौष्टिक और विविध खाद्य वस्तुओं की ओर संसाधन ले जाना चाहिए। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि मुद्रा-आय और निर्यात क्षमता भी मजबूत होगी।

3. अवसंरचना और रसद (Infrastructure & Logistics)

कृषि आपूर्ति श्रृंखला सुधार, भंडारण क्षमता, मंडी सुधार और ठंडा चैन अवसंरचना का विस्तार। डिजिटल किसान रजिस्ट्रेशन और किसान-डेटा एकीकृत प्रणाली से योजनाओं और सब्सिडी वितरण की दक्षता में सुधार।

उदाहरण: उत्तर प्रदेश में किसान रजिस्ट्री अभियान किसानों के डेटा को एकीकृत करने में प्रगति पर है।

4. सतत और पर्यावरण-अनुकूल कृषि (Sustainable & Climate-Smart Agriculture) [9]

जलवायु बदलाव, भूमि क्षरण, और जल संकट से निपटने हेतु सतत कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाएं। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकें और जल प्रबंधन को प्राथमिकता देना। यह रणनीति खाद्य सुरक्षा और दीर्घकालिक संसाधन रक्षा दोनों के लिए आवश्यक है।

5. किसान-केंद्रित कार्यक्रम और वित्तीय सहायता

MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में सुधार, कृषि बीमा, और वित्तीय पहुँच सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि जैसे कार्यक्रमों से किसानों की बदली हुई आय स्तिथि को समर्थन मिलता है। (तथा प्रधानमंत्री द्वारा बड़े पैमाने पर वित्तीय हस्तांतरण योजनाएँ) [8]

कृषि विकास हेतु आवश्यक रणनीतियाँ

1- कृषि में तकनीकी नवाचार

तकनीक कृषि परिवर्तन की सबसे बड़ी कुंजी है।

2047 तक कृषि को स्मार्ट और डिजिटल बनाना अनिवार्य है।

- प्रिसिजन फार्मिंग:
  मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सेंसर, ड्रोन और GIS आधारित खेती।
- डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म:
  किसान को मौसम, बाजार और फसल सलाह की रियल-टाइम जानकारी।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):
  फसल रोग पहचान, उत्पादन पूर्वानुमान।

तकनीक से लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और जोखिम कम होगा।

चित्र 1. स्मार्ट कृषि में ड्रोन, रोबोटिक्स, IoT सेंसर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परिशुद्ध कृषि तकनीकों का एकीकृत उपयोग।

2 - कृषि अनुसंधान एवं विकास (R&D)

भारत में कृषि अनुसंधान पर GDP का लगभग 0.4 प्रतिशत खर्च किया जाता है, जबकि विकसित देशों में यह 1–2 प्रतिशत तक है। 2047 के लक्ष्य हेतु—

- कृषि अनुसंधान निवेश को बढ़ाना होगा
- ICAR और कृषि विश्वविद्यालयों को मजबूत करना होगा
- जलवायु-सहिष्णु बीजों का विकास करना होगा

फसल विविधीकरण और पोषण-आधारित कृषि

धान-गेहूँ आधारित प्रणाली ने उत्पादन तो बढ़ाया, परंतु—

- जल संकट
- मृदा क्षरण
- पोषण असंतुलन

को जन्म दिया।

अब आवश्यकता है—

- दालें, तिलहन, मोटे अनाज (श्रीअन्न)
- बागवानी और पशुपालन
- मत्स्य पालन

को बढ़ावा देने की।

3 - सतत एवं जलवायु-स्मार्ट कृषि[5]

जलवायु परिवर्तन कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। इससे निपटने के लिए—

- सूक्ष्म सिंचाई
- जैविक और प्राकृतिक खेती
- कार्बन-स्मार्ट कृषि

को अपनाना आवश्यक है।

4 - कृषि अवसंरचना और बाजार सुधार

- भंडारण और कोल्ड चेन
- ई-NAM और डिजिटल मंडियाँ
- मूल्य संवर्धन और फूड प्रोसेसिंग

किसानों की आय दोगुनी करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

5 - किसान-केंद्रित नीतियाँ

कृषि विकास का केंद्र किसान होना चाहिए—

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुधार
- फसल बीमा
- संस्थागत ऋण
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

से किसानों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ेगी।

6 - कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

कृषि का विकास सीधे-सीधे—

- ग्रामीण रोजगार
- पलायन में कमी
- सामाजिक स्थिरता

से जुड़ा हुआ है। 2047 तक ग्रामीण भारत को समृद्ध बनाए बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है।

प्रमुख खोज (Major Findings)

- कृषि विकास के बिना विकसित भारत की परिकल्पना संभव नहीं है।
- तकनीकी नवाचार से उत्पादन और आय में वृद्धि होती है।
- MSP एवं बाजार संरचना में सुधार की आवश्यकता है।
- कृषि अनुसंधान में निवेश अपर्याप्त है।
- जलवायु परिवर्तन भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है।
- डिजिटल कृषि में अपार संभावनाएँ हैं, किंतु समावेशन आवश्यक है।

सुझाव (Suggestions)

- कृषि अनुसंधान में निवेश को GDP के न्यूनतम 1% तक बढ़ाया जाए।
- छोटे किसानों के लिए तकनीकी सब्सिडी दी जाए।
- MSP को कानूनी समर्थन देने पर विचार किया जाए।
- जल-संरक्षण आधारित कृषि को बढ़ावा दिया जाए।
- कृषि-आधारित स्टार्टअप और FPOs को प्रोत्साहन मिले।
- ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अनिवार्य किए जाएँ।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान महत्त्वपूर्ण है। 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राष्ट्रीय दृष्टि में कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि $1 ट्रिलियन कृषि अर्थव्यवस्था और उच्च निर्यात क्षमताओं के माध्यम से सतत विकास को भी साधेगा। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि विकास की भूमिका निर्णायक है। कृषि केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिरता, आर्थिक समावेशन और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। यदि कृषि को तकनीकी, आर्थिक एवं नीतिगत रूप से सशक्त किया जाए, तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि वैश्विक कृषि नेतृत्व भी स्थापित कर सकेगा।

संदर्भ सूची

[1]. Government of India. Economic Survey of India 2022–23. Ministry of Finance, 2023.
[2]. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Agricultural Statistics at a Glance. Government of India, 2022.
[3]. Indian Council of Agricultural Research. Vision 2050: Indian Agriculture. ICAR, 2021.
[4]. NITI Aayog. Doubling Farmers' Income: Strategy and Roadmap. Government of India, 2021.
[5]. Food and Agriculture Organization. Climate-Smart Agriculture Sourcebook. FAO, 2020.
[6]. World Bank. Transforming Agriculture for Sustainable Growth in India. World Bank Publications, 2022.
[7]. NSSO. Situation Assessment of Agricultural Households in India. Government of India, 2019.
[8]. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. PM-KISAN Scheme Guidelines. Government of India, 2023.
[9]. Down To Earth. "Diversification of Indian Agriculture for Sustainable Growth." Down To Earth, 2022.
[10]. Newsonair. "Five Percent Annual Growth Needed in Agriculture for Viksit Bharat 2047." All India Radio, 2023.
[11]. www.jagran.com
[12]. www.drishtiias.com
[13]. www.pib.gov.in

Cite this Article:

*धनंजय कुमार मौर्य. **(2026).** "कृषि विकास से विकसित भारत की ओर: 2047 के लक्ष्य हेतु आवश्यक रणनीतियां". International Journal of Multidisciplinary Research in Arts, Science and Technology (IJMRAST), 4(8), 7–13.*

***Journal URL:** https://ijmrast.com/ **DOI:** https://doi.org/10.59828/ijmrast.v4i8.305*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non-Commercial 4.0 International License.
© The Author(s) 2026. IJMRAST Published by Surya Multidisciplinary Publication.

***Disclaimer/Publisher's Note**: The author(s) are solely responsible for the content and claims of this article. The publisher and editors assume no legal liability for any errors, copyright violations, or damages arising from its use.*